131

VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R N
16 SEP 2018
NO. 03
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1071)

Name of Candidate	सुनिल कुमार धनवन्ता		
Medium Eng./Hindi	हिन्दी	Registration Number	109506
Center	KB	Date	16/09/18

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

M-1/4, Plot No-A-12/13, Ist Floor, Ansal Building, Dr. Vidya Sagar Homeopathic Clinic, Mukherjee Nagar, Delhi-110009

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. It has been argued that over the years there has been a steady decline in the efficacy of Parliament as an institution of accountability. Analyse and also suggest appropriate measures to address the relevant concerns.

(150 words) 10

यह तर्क दिया जाता है कि वर्षों से एक जवाबदेह संस्था के रूप में संसद की प्रभावकारिता में निरंतर गिरावट आई है। विश्लेषण कीजिए और साथ ही, प्रासंगिक चिंताओं का समाधान करने हेतु उचित उपाय भी सुझाइए।

इस वर्ष के बजट सत्र में लगातार व्यवधान के कारण संसद की प्रभावकारिता पर प्रश्न चिह्न लगाये जा रहे हैं

प्रभावकारिता में गिरावट के कारण

(i) संसद में अनावश्यक गतिरोध बनाना
(ii) राजनीतिज्ञों के मध्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति असंवेदनशीलता
(iii) संसद के कार्यों के मूल्यांकन के लिए संस्थागत संरचना का अभाव

प्रभावकारिता में गिरावट की हानियां

(i) विधायी कार्यों में रुकावट के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया का धीमा होना

→ गतिरोध के कारण विधेयकों पर अपर्याप्त बहस

→ संसद के गतिरोध के कारण आर्थिक हानि

→ संसद की गरिमा में गिरावट

समाधान के उपाय -

→ सरकार द्वारा विपक्षी पार्टियों की चिन्ताओं को पहचानकर पर्याप्त बहस का मंच उपलब्ध कराना तथा विपक्ष द्वारा भी इसमें सहयोग देना

→ संसद के कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन ताकि नेताओं पर नैतिक दबाव बनाया जा सके

इसके साथ ही राजनेताओं को इस पवित्र संस्था की गरिमा को बचाये रखने के लिए संवेदनशील होना होगा जिसमें जनता का प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Panchayati raj institutions (PRIs) are simultaneously a remarkable success and a staggering failure, depending on the goalposts against which they are evaluated. Discuss. **(150 words) 10**

पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) एक उल्लेखनीय सफलता होने के साथ-साथ स्तब्धकारी विफलता भी हैं, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इनका मूल्यांकन किन लक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। चर्चा कीजिए।

73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई

सफलता के बिन्दु-

(i) समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में वृद्धि

(ii) महिला आरक्षण की बदौलत इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी लगभग 42% है

(iii) लोग प्रशासन से भयभीत होने के बजाय

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

उसमें भागीदारी करने का प्रयास कर रहे हैं

(iv) सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा इत्यादि का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हुआ है

असफलताएँ

(i) पंचायतों की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का निम्न स्तर पर होना

(ii) पंचायतों में अभी भी समाज में उच्च वर्ग व बाहुबलियों का नियंत्रण व्याप्त

(iii) महिलाओं को वास्तविक भागीदार बनाने के बजाय केवल सांकेतिक भागीदारी जैसे सरपंच पति

इसलिए पंचायतों की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. The Comptroller and Auditor General of India (CAG) is more than just the keeper of our national accounts; it is also a conscience-keeper and a watchdog. Examine the statement in light of making the auditing process more effective. **(150 words) 10**

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) केवल हमारे राष्ट्रीय खातों के रक्षक से कहीं अधिक है; यह अंत:करण का संरक्षक और वॉचडॉग (प्रहरी) भी है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केन्द्र व राज्य सरकार के खातों की लेखापरीक्षा का अधिकार प्राप्त है

व्याप्त चुनौतियां

(i) CAG की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूर्वक्रियात्मक न होकर प्रतिक्रियात्मक है अर्थात घटना के घटित होने के पश्चात उसका खुलासा किया जाता है।

(ii) CAG की रिपोर्ट ~~क~~ पर लोक लेखा समिति के विचार करने के पश्चात जब रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय तक घटना पुरानी हो चुकी

होती है जिस पर व्यापक जन-विमर्श नहीं हो पाता

~~अत~~ ले
लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने के उपाय.

(i) ~~@~~ CAG द्वारा सरकार के लेखों की पूर्वक्रियात्मक समीक्षा तथा लेखा मानकों का निर्धारण

(ii) CAG की रिपोर्ट पर तुरंत विचार किया जाना

(iii) CAG की अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाया जाना

इसी के साथ CAG द्वारा त्रुटिखोजी संस्था के स्थान पर लेखापरीक्षा के अभिभावक के तौर पर कार्य करना चाहिए ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. The concern for transparency in political funding is at odds with the Electoral Bond Scheme notified by the government. Critically discuss.

(150 words) 10

राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता की चिंता सरकार द्वारा अधिसूचित चुनावी बॉण्ड योजना से असंगत है। समालोचनात्माक चर्चा कीजिए।

हाल ही में सरकार द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा चंदा प्राप्त करने के लिए चुनावी बॉड को अनिवार्य कर दिया गया

चुनावी बॉड के प्रावधान

(i) २००० रुपये से अधिक का चन्दा नकद के बजाय चुनावी बॉड के माध्यम से

(ii) चुनावी बॉड को कोई भी भारतीय व्यक्ति या संस्था बैंक में डिजिटल भुगतान या चेक के माध्यम से खरीद सकती है

(iii) राजनीतिक दल को 15 दिन की अवधि में इसे अपने खाते में भुनाना होगा

चुनावी बॉड के पक्ष में तर्क

→ डिजिटल भुगतान के कारण अवैध धन का प्रयोग नहीं हो सकेगा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ चन्दा प्रदान करने वाले को 'KYC' मानकों का पालन करना होगा

नकारात्मक पक्ष.

→ इसमें चन्दा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी जिससे राजनीतिक दलों एवं कंपनियों के मध्य सांठगांठ में वृद्धि हो सकती है

→ कंपनी को अपने बहिखातों में राजनीतिक दल का नाम दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है तथा वे कितनी भी राशि दान कर सकते है इससे सरकारी नीतियों के प्रभावित होने की आशंका है

→ अपारदर्शिता

इसलिए राजनीतिक वित्तपोषण को पारदर्शी बनाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान अत्यावश्यक है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Lobbying in India exists in a perennially grey legal and policy arena. In this context, discuss the need to formally recognize and regulate lobbying in India. **(150 words) 10**

भारत में लॉबिंग हमेशा से ही विधिक और नीतिगत क्षेत्र में अपरिभाषित रूप से विद्यमान रही है। इस संदर्भ में, भारत में लॉबिंग को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने और विनियमित करने की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

राजनीतिक नेतृत्व पर अनेक तरीकों से दबाव बनाकर नीतियों को अपने पक्ष में करने की प्रक्रिया लॉबिंग कहलाती है।

भारत में लॉबिंग को औपचारिकता प्रदान करने के पक्ष में तर्क

→ अमेरिका जैसे देशों में लाबिंग को कानूनी वैधता प्राप्त है अतः भारत में भी इसको कानूनी बनाया जा सकता है

→ लाबिंग को औपचारिक बनाने से ~~सब~~ एक कंपनी या संगठन को लाभ के बजाय सभी कंपनियों को फायदा होगा

→ इससे देश के कारोबारी माहौल में सकारात्मकता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आने की संभावना है.

विपक्ष में तर्क.

(i) लाबिंग अनैतिक है तथा इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है

(ii) क्रोनी पूँजीवाद में वृद्धि होने की संभावना है जिससे सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल सकती है

(iii) सामाजिक विकास व न्याय के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना।

इसलिए लाबिंग को औपचारिक बनाने एवं विनियमित करने से पूर्व इसके पक्ष एवं विपक्ष पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. More than a decade after it was passed, the implementation of the RTI Act leaves much to be desired. Comment. Also discuss the issues associated with the recent proposals to amend the RTI Act. **(150 words) 10**

पारित होने के एक दशक से भी अधिक समय बाद, RTI अधिनियम के कार्यान्वयन में काफी कुछ वांछित है। टिप्पणी कीजिए। RTI अधिनियम में संशोधन के हालिया प्रस्तावों से जुड़े मुद्दों की भी चर्चा कीजिए।

भारत में नागरिकों के सूचना प्रदान होने की रक्षा करने एवं सरकार में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए RTI अधिनियम लागू किया गया

प्रमुख मुद्दे-

(i) राजनीतिक दलों व न्यायपालिका का RTI के दायरे से बाहर होना

(ii) केन्द्रीय सूचना आयोग व राज्य सूचना आयोग की शक्तियों का अप्रभावी होना

(iii) सूचनाओं के पूर्वक्रियात्मक प्रकटीकरण का निम्न स्तर

हालिया संशोधन से संबन्धित मुद्दे

(i) इसमें व्हिसल ब्लोअर्स को सुरक्षा प्रदान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

करने के प्रावधानों में शिथिलता का प्रावधान है जिससे RTI सक्रिय लोगों के जीवन पर संकट आ सकता है

(iii) सूचनाओं के स्वप्रकटन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है

(iii) राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाने का कोई प्रयास नहीं

(iv) केन्द्रीय सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के सेवा-शर्तों, वेतन व भत्तों के निर्धारण की शक्तियां केन्द्र सरकार को देने से राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि हो सकती है

इसलिए वर्तमान में सूचना प्राप्ति के अधिनियम को कमजोर बनाने के बजाय सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Critically discuss the evolving policy on reservation in promotions in India with special focus on its ability to meet the objectives of social justice.

(150 words) 10

सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने की इसकी क्षमता पर विशेष बल देते हुए भारत में प्रोन्नति में आरक्षण पर विकसित हो रही नीति की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को विद्यमान नीतियों के अनुसार प्रोन्नति करने का आदेश दिया गया है

प्रोन्नति में आरक्षण के पक्ष में तर्क

(i) उच्च पदों पर समाज के कमजोर वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को कम करने में सहायता मिलेगी जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा

(ii) सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागराज वाद (२००६) में प्रोन्नति में आरक्षण का समर्थन

(iii) अनेक समितियों द्वारा इसका समर्थन

(iv) संविधान के प्रावधानों को लागू करने हेतु

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विपक्ष में तर्क

(i) सरकारी दक्षता में नकारात्मकता के समावेश होने की आशंका

(ii) सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी वाद में प्रोन्नति में आरक्षण पर रोक

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. India produces enough food for its people, but not all people get enough food to eat. Discussing this paradox, highlight some of the major interventions taken in the past few years in this regard. **(150 words) 10**

भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान उत्पादित करता है, फिर भी सभी लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। इस विरोधाभास की चर्चा करते हुए, इस संबंध में विगत कुछ वर्षों में उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालिए।

भारत की वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 100वी रैंक यहा भोजन उपलब्धता के निम्न स्तर को दिखाती है।

भारत खाद्यान्न का व दालों का अग्रणी उत्पादक है

लोगों को खाना न मिलने के कारण-

(i) खाद्यान्न उत्पादन का असमान वितरण

(ii) भंडारण व परिवहन की सुविधा के अभाव के कारण खाद्यान्न बर्बादी

(iii) गरीब लोगों के पास क्रय शक्ति का अभाव

(iv) सरकारी नीतियों की अप्रभाविता तथा प्रशासनिक अक्षमता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार के कदम:

(i) राष्ट्रीय पोषण मिशन

(ii) मिड डे मिल स्कीम

(iii) मनरेगा

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार के माध्यम से खाद्य वितरण

(v) खाद्य बर्बादी को रोकने के लिए भण्डारण सुविधा

9. India sees Indian Ocean as not just a water body, but a global stage for continued economic, social, and cultural dialogue. Elaborate.**(150 words) 10**

भारत, हिंद महासागर को मात्र एक जल निकाय के रूप में ही नहीं, बल्कि निरंतर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के एक वैश्विक मंच के रूप में भी देखता है। सविस्तार वर्णन कीजिए।

हिन्द महासागर भारत के दक्षिण में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण महासागर है

आर्थिक महत्व

(i) तेल व गैस संसाधनों की प्रचुरता
(ii) जैविक व अजैविक संसाधन
(iii) पॉली मैटेलिक नोड्यूल्स
(iv) व्यापार मार्गों की उपस्थिति

सामाजिक महत्त्व

(i) मत्स्यन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा
(ii) रोजगार की उपलब्धता

सांस्कृतिक महत्व.

(i) अनेक अफ्रीकी व दक्षिण-पूर्वी देशों के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ सांस्कृतिक संबंध बनाने में सहायक

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. In the context of India taking greater responsibility in management of the global commons, there has been a shift in India's climate change negotiation stance. In this context, analyze the evolution of India's climate policy. **(150 words) 10**

भारत द्वारा ग्लोबल कॉमंस के प्रबंधन में बृहत्तर दायित्व ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में, भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधित वार्ता दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। इस संदर्भ में, भारत की जलवायु नीति के विकास का विश्लेषण कीजिए।

→ भारत द्वारा बहुपक्षीय मंचों का प्रयोग।

→ चीन के साथ मिलकर इन मुद्दों में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन

→ पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्धता

→ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना करना

→ अमेरिका पर दबाव बनाने का प्रयास करना।

भारत की जलवायु नीति.

(i) NPCC – 8 मिशन

(ii) INDC की घोषणा

(iii) स्मार्ट सीटी मिशन, सौर गठबंधन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Highlighting the constitutional role of the Finance Commission (FC), discuss the issues which are being debated w.r.t. terms of reference (ToR) of the 15th Finance Commission. **(250 words) 15**

वित्त आयोग (FC) की संवैधानिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जिनपर 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (ToR) के संदर्भ में बहस की जा रही हैं।

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले, जब आवश्यक हो, एक वित्त आयोग के गठन का अधिकार दिया गया है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके समक्ष अनेक मुद्दे उपस्थित हैं

~~→ सर्वप्रथम वित्त आयोग के समक्ष यह सबसे~~

वित्त आयोग को संविधान द्वारा प्रदत्त आदेश.

→ केन्द्र सरकार के करों के शुद्ध आगमों का विभाजन पर सुझाव

→ केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के बारे में संस्तुति करना

→ पँचायतीराज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्त प्रदान करने संबंधी मुद्दों व उपायों का सुझाव देना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15 वें वित्त आयोग के समक्ष मुद्दे

→ इस बात पर विचार करना कि केन्द्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा किस फार्मूले के तरीके से किया जाए

→ वित्त आयोग ने करों के बंटवारे के सूत्र में 2011 के जनगणना के आंकड़ों के भारांश को बढ़ाने की बात कही है। परन्तु इस बात से दक्षिण भारत के अनेक राज्य असंतुष्ट है क्योंकि इस कदम से उत्तरी भारत को राजस्व का अनुचित हिस्सा प्राप्त होगा जबकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बल नहीं दिया।

→ वित्त आयोग द्वारा पँचायतीराज संस्थाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए यह बात कही जा रही है कि उन राज्यों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की है। इस क्रम से अनेक राज्यों को लाभ व अनेक को हानि होने की संभावना है

इस प्रकार वित्त आयोग के समक्ष संविधान में प्रदत्त उसके कर्तव्यों के अनुसार भारत में ~~संघीय~~ वित्तीय संघवाद के ढांचे को सुरक्षित रखने का दायित्व है जिस पर व्यापक विचार-विमर्श व संवाद आवश्यक है ताकि प्रमुख मुद्दों का समाधान हो सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The spirit of the constitution of India represents a synthesis of Indian values, democratic and socialist movements in west and our independence movement. Elucidate. **(250 words) 15**

भारतीय संविधान की भावना भारतीय मूल्यों, पश्चिम के लोकतांत्रिक व समाजवादी आंदोलनों एवं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के संश्लेषण को निरूपित करती है। स्पष्ट कीजिए।

भारतीय संविधान संसार का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है जिसमें भारतीय एवं विदेशी लोकतांत्रिक, समाजवादी मूल्यों का समावेश है।

भारतीय मूल्य -

→ संविधान में भारतीय मूल्यों के अनुसार नारी की सुरक्षा करने का दायित्व (अनु. 51A) नागरिकों को दिया गया है

→ प्रकृति प्रेम के अनुसार पर्यावरण संरक्षण का दायित्व {अनु. 48A तथा 51A (g)}

→ वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धान्त

पश्चिम के लोकतांत्रिक मूल्य -

→ धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति इत्यादि की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वतंत्रता [अनु. 19 (1)]

→ समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

→ लोकतांत्रिक गणतंत्रवाद का सिद्धान्त प्रस्तावना में उल्लेखित है

→ अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धान्त लिया गया है

→ सोवियत संघ से 'मौलिक कर्तव्यों' का सिद्धान्त क्योंकि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आवश्यक है

→ ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था का सिद्धान्त

समाजवादी आंदोलनों के सिद्धान्त

→ नीति निर्देशक तत्वों एवं प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लेख

→ समाज के कमजोर वर्गों जैसे OBC, SC व ST को विशेष प्रावधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ प्रबन्धन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान (अनु. 43A)

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य.

→ गांधीजी का ग्राम पंचायत का सिद्धान्त (अनु. 40 तथा भाग IX)

→ समाजवाद का सिद्धान्त (प्रस्तावना)

→ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त

→ छूआछूत की समाप्ति

इस प्रकार भारतीय संविधान अनेक सिद्धान्तों व मूल्यों का संश्लेषित रूप है जिसको महान संविधानविद ग्रेनविले ऑस्टिन ने सामाजिक न्याय का एक जीता - जागता दस्तावेज कहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. What is the importance of an independent judiciary in a democracy? Highlight the safeguards in our political-constitutional setup to ensure the independence of judiciary. **(250 words) 15**

लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु हमारी राजनीतिक-संवैधानिक व्यवस्था में निहित रक्षोपायों पर प्रकाश डालिए।

भारत में सरकार के तीसरे अंग के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है जिसको स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत रखा है।

* स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व.

(i) स्वतंत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदविमुक्ति में राजनीतिक व प्रशासनिक हस्तक्षेप न होने के कारण पारदर्शिता व न्यायपालिका की ~~सुचिता~~ शुचिता में वृद्धि

(ii) न्यायाधीश बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष एवं तथ्यापरक न्याय प्रदान करने में सक्षम होते हैं जिससे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोकतंत्र को और अधिक मजबूती प्राप्त होती है

(iii) न्यायपालिका के निर्णयों ~~कर~~ की आलोचना पर रोक के कारण न्यायाधीशों पर अनुचित दबाव में कमी आती है जिससे वे निष्पक्ष होकर अपना निर्णय दे सकते हैं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक व राजनीतिक प्रावधान

→ न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यूनतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप क्योंकि इनकी नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से की जाती है (अनुच्छेद १२४)

→ न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की संचित निधि पर निर्भर होते है जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता

→ संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर कोई बहस नहीं हो सकती जब तक कि उन पर कोई महाभियोग की प्रक्रिया न चल रही हो

→ अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए ~~दण्डित~~ दण्डित करने की शक्ति प्राप्त है

परन्तु समय-समय पर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न-चिह्न लगाये जाते रहे है जिनका तत्काल प्रभाव से सर्वसम्मति द्वारा समाधान करने की आवश्यकता है ताकि भारतीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत किया जा सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Even though Indian federalism has matured quite a bit, with states having far greater control of their economic and political management, serious structural problems still remain. Discuss. **(250 words) 15**

यद्यपि भारतीय संघवाद काफ़ी हद तक परिपक्वता प्राप्त कर चुका है जहाँ राज्यों को अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधन पर पर्याप्त नियंत्रण है, तथापि गंभीर संरचनात्मक समस्याएं अब भी विद्यमान हैं। चर्चा कीजिए।

भारतीय राजव्यवस्था में स्वतंत्रता के पश्चात संघवाद के ढांचे का अनुकरण किया गया जिसमें सरकार की शक्तियों को राज्यों एवं संघ सरकार में विभाजित किया गया है।

कालान्तर में राज्यों को इस ढांचे के अंतर्गत पर्याप्त आर्थिक व राजनीतिक शक्तियाँ प्रदान की गई है जैसे अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी तथा केन्द्र के कर राजस्व में राज्यों की 42% हिस्सेदारी इसका प्रमाण है।

परन्तु इसके बावजूद भी भारतीय

संघात्मक व्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित ~~संस्था~~ संरचनात्मक समस्याएं विद्यमान हैं.

→ संघ सरकार राज्यपाल के माध्यम से राज्यों की सरकार के स्थायित्व एवं संचालन को प्रभावित करने का प्रयास करती है जैसे कर्नाटक विधानसभा का मामला

→ केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मियों के माध्यम से राज्य के प्रशासन पर पकड़ बनाये रखने का प्रयास करती है जिससे अधिकांश राज्य असंतुष्ट रहते हैं।

→ संघ ~~राज्य~~ सरकार केन्द्रीय सशस्त्र बलों की नियुक्ति (deployment) के माध्यम से राज्य में दखल देती है

→ संघ सरकार वित्त आयोग तथा अन्य वित्तीय अनुदानों के माध्यम से राज्य

की वित्तीय स्वायत्तता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है जो संघवाद की भावना के विरुद्ध प्रतीत होता है

→ केन्द्र सरकार राज्यों की सहमति के बिना उनके नाम व सीमा में परिवर्तन कर सकती है (अनुच्छेद 3)

→ ~~सर केन्द्र सरकार~~ राज्यसभा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।

इसलिए संघवाद की मजबूती के लिए उपर्युक्त समस्याओं का तत्काल निवारण आवश्यक है जिसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद, क्षेत्रीय परिषदों इत्यादि मंचों का प्रयोग किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. The recent amendments to the Prevention of Corruption Act, 1988 strike a balance between enforcement overzealousness and the need for stringent action against corrupt public servants. Discuss. **(250 words) 15**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में हालिया संशोधन प्रवर्तन के प्रति अतिउत्साह और भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की आवश्यकता के बीच एक संतुलन कायम करता है। चर्चा कीजिए।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल के करप्शन परसेप्शन इण्डेक्स में भारत के अत्यन्त निम्न प्रदर्शन से भारत में भ्रष्टाचार की व्यापकता सिद्ध होती है।

भारत में भ्रष्टाचार के क्रियाकलापों पर नियंत्रण हेतु संथानम समिति के बाद 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित किया गया जिसके भ्रष्ट सरकारी व निजी व्यक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधान

→ इसमें किसी लोकसेवक पर भ्रष्टाचार संबंधी कार्रवाही करने से पूर्व संबन्धित विभाग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान को सेवानिवृत्त लोकसेवकों हेतु भी लागू किया गया है

→ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों पर अंकुश लगाने के लिए फास्ट ट्रायल न्यायालयों के निर्माण का प्रावधान

→ संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान

संशोधन के पक्ष में विचार -

→ इससे ईमानदार लोकसेवकों को अनावश्यक उत्पीड़न से सुरक्षा ~~प्राप्त~~ प्राप्त होगी

→ लोकसेवक बिना किसी भय के नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होंगे

→ फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विपक्ष में विचार -

→ सरकार अपने प्रभाव का प्रयोग कर भ्रष्ट लोकसेवकों को बचाने का प्रयास कर सकती है जिसमे प्रशासन में भ्रष्टाचार के बढ़ने की आवश्यकता है

→ भ्रष्टाचार में वृद्धि के कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में नकारात्मक परिवर्तन संभव है

इस प्रकार इस संशोधन के माध्यम से अधिनियम को संतुलित करने का प्रयास किया गया परन्तु इसकी नकारात्मकताओं से बचने के लिए सरकार व कानून प्रवर्तन एजेंसियों निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से इसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Identifying the various issues plaguing the voluntary sector in India, discuss the need for a national accreditation agency to overcome them. Discuss.

(250 words) 15

भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र को अवरुद्ध करने वाले विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिए एवं इन पर काबू पाने हेतु एक राष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसी की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

स्वैच्छिक संगठन ऐसे संगठन होते है जो अपनी स्वेच्छा से बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए समाज की सेवा करने का प्रयास करते हैं।

स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने वाले प्रमुख मुद्दे-

(i) इनके पास वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है जो इनके कार्यक्रमों के संचालन में बाधक होता है

(ii) पर्याप्त सरकारी सहायता का अभाव

(iii) इनके विनियमन हेतु उपयुक्त संस्था एवं विधिक प्रावधानों का अभाव जिसके

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

फलस्वरूप ये गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने का प्रयास कर सकते हैं

(iv) कई स्वैच्छिक संगठनों पर मनी लॉड्रिंग का आरोप भी लगाया जाता है।

(v) कई गैर- सरकारी संगठनों के वित्त पोषण में भारी अनियमितता तथा विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (FCRA) का अप्रभावी ~~क्रियान्व~~ क्रियान्वयन

राष्ट्रीय प्रमाण एजेंसी की आवश्यकता

(i) स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्राप्त करने के लिए तथा इनके विनियमन के लिए वर्तमान में संस्थागत संरचना के अभाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को पूरा करने के लिए

(ii) इनके वित्त पोषण व सरकारी योजनाओं में भागीदारी को विनियमित करने के लिए

(iii) गैर-कानूनी कार्यों में लिप्त होने पर इनके विरुद्ध जांच करने एव इनके लाइसेंस को रद्द करने के लिए

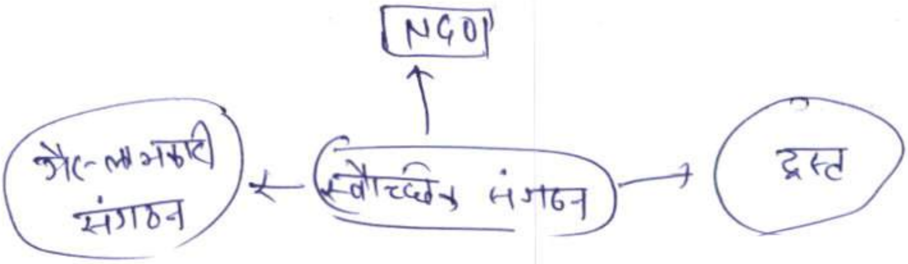

इस प्रकार यह एजेंसी स्वैच्छिक क्षेत्र की गुणवत्ता को बनाये रखने तथा सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बनाये रखने में सहायक होगी।

17. Given the importance of a teacher in affecting the learning outcomes of children, discuss the problems in the present system of teacher training in India. How can these be addressed? **(250 words) 15**

बच्चों के अधिगम परिणाम को प्रभावित करने में शिक्षकों के महत्व को देखते हुए, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली में विद्यमान समस्याओं पर चर्चा कीजिए। इनसे कैसे निपटा जा सकता है?

NGO प्रथम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)' के अनुसार भारत में बच्चों में अधिगम क्षमता निम्न स्तर पर है। इसे प्रभावित करने में शिक्षक व शिक्षक प्रशिक्षणों की पर्याप्त भूमिका होती है।

भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की वर्तमान प्रणाली में विद्यमान समस्याएं

→ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अवसंरचना का निम्न स्तर है।

→ शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पुराने समय के हैं जिसमें नयी परिस्थितियों के अनुसार

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शिक्षण का प्रावधान नहीं है।

→ शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के शिक्षण का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता जिससे वे छात्रों के बीच एक प्रभावी शिक्षण प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं।

→ शिक्षकों को छात्र मनोविज्ञान का खास प्रशिक्षण नहीं दिया जाता जिसके फलस्वरूप शिक्षक छात्रों के साथ एक सहयोगी माहौल पैदा नहीं कर पाते जो प्रभावी शिक्षण हेतु अत्यावश्यक है।

→ शिक्षक प्रशिक्षण के संबन्ध में सरकार के पास स्पष्ट नीति का अभाव है तथा विद्यमान योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसके समाधान के लिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निम्नलिखित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है-

(i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अवसंरचनात्मक व गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना।

(ii) शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाकर डिजिटल प्रशिक्षण का भी प्रावधान।

(iii) शिक्षकों को छात्र मनोविज्ञान का प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(iv) सरकार द्वारा एक परिणामोन्मुखी स्पष्ट नीति का निर्माण व क्रियान्वयन आवश्यक है

इसी को देखते हुए सरकार ने 'दीक्षा पोर्टल' तथा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को शामिल करने जैसे प्रयास किये गये है जिन पर और अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है।

18. The implementation of a scheme with such scale and benefit as Ayushman Bharat is likely to face many obstacles. Critically discuss. **(250 words) 15**

आयुष्मान भारत जैसी अति व्यापक और लाभकारी योजना के कार्यान्वयन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

सरकार द्वारा भारत की गरीब जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 'आयुष्मान भारत' नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

इस कार्यक्रम के दो घटक हैं-

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।

→ इसमे देश की लगभग 40% जनसंख्या को कवर करते हुए सार्वजनिक व निजी दोनों अस्पतालों को शामिल किया गया है

(ii) 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

एवं देखभाल केन्द्रों में परिवर्तित करने का प्रावधान जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा सुनिश्चित की जा सके।

आयुष्मान भारत कार्यक्रम के समक्ष बाधाएं

→ इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए कोई स्पष्ट रूप-रेखा निर्धारित नहीं की गई है जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्त के अभाव को जन्म दे सकता है।

→ इसके लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा न होने के कारण इसके सटीक लक्ष्यकरण में बाधा आ सकती है।

→ 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्रों के निर्माण के लिए अति उच्च स्तर पर अवसंरचना व वित्त की आवश्यकता होगी जिसके

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

लिए ~~राज्य पर~~ राजकोष पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है

→ ~~इस~~ सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षित चिकित्सकों व कर्मियों की स्पष्ट कमी है जिनके बिना इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती

→ इससे सार्वजनिक चिकित्सालयों की उपेक्षा की संभावना है क्योंकि लोग निजी चिकित्सालयों को उपचार प्राप्त करने हेतु ज्यादा ~~और~~ वरीयता दे सकते हैं

अतः भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति सुधारने तथा सतत विकास लक्ष्य 4 की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त वित्त व कर्मचारी बल का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Given the fact that India cannot match China's financial clout, it is seen to be diversifying the ways in which it can enhance cooperation and promote its diplomatic profile in Africa. Discuss. **(250 words) 15**

इस तथ्य को देखते हुए कि भारत, चीन के वित्तीय प्रभुत्व की बराबरी नहीं कर सकता, यह देखा जा रहा है कि भारत ऐसे विविध तरीके अपना रहा है जिसके तहत यह अफ्रीका में सहयोग में वृद्धि और अपनी कूटनीतिक सक्रियता को बढ़ावा दे सके। चर्चा कीजिए।

पिछले कुछ वर्षों से चीन अफ्रीका महाद्वीप में भारी वित्तीय निवेश के माध्यम से अपनी उपस्थिति को निरन्तर सुदृढ़ कर रहा है जो भारत के समक्ष एक स्पष्ट चुनौति प्रस्तुत करता है क्योंकि भारत के पास इतनी वित्तीय शक्ति विद्यमान नहीं है।

इसलिए भारत वित्तीय निवेश के साथ-साथ निम्नलिखित प्रयास करने का प्रयास कर रहा है-

(i) अफ्रीका के युद्धग्रस्त व अशांत क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में <u>शांति बल</u> भेजकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करना

(ii) अफ्रीकी देशों को आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद

से निपटने के लिए मानवीय सहायता एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करना

(iii) हाल ही में भारत द्वारा युगांडा को 200 गायें भेंट की गई ताकि वहां पर पोषण की स्थिति को सुधारा जा सके

(iv) भारत द्वारा अफ्रीकी देशों के युवकों को शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक शिक्षण संस्थानों व कौशल केन्द्रों की स्थापना की गई है

(v) अफ्रीकी विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति प्रदान करना

(vi) अफ्रीकी विकास बैंक की भारत में आयोजित बैठक के दौरान इस बैंक के लिए 'लाइन ऑफ क्रेडिट' के माध्यम से वित्तीय सहायता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रदान करना

(vii) हथियारों की तस्करी व पाइरेसी में कमी के लिए अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग करना

(viii) जापान के साथ मिलकर अफ्रीका में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अफ्रीकी विकास कॉरिडोर के निर्माण हेतु योजना

(ix) पैन अफ्रीका ई- क्रान्ति का क्रियान्वयन

इस प्रकार जहां चीन अपनी वित्तीय शक्ति एवं सैन्य शक्ति के माध्यम से अफ्रीका पर पकड़ बनाने का प्रयास कर रहा है तो भारत को भी अफ्रीका के महत्व को ध्यान में रखते हुए निरन्तर प्रयासों की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Discuss how American sanctions on its adversaries affect India. Taking the example of CAATSA, analyse how India can shield its strategic interests in face of such sanctions. **(250 words) 15**

चर्चा कीजिए कि अमेरिका द्वारा अपने विरोधियों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध भारत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। CAATSA का उदाहरण लेते हुए, विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार भारत ऐसे प्रतिबंधों की स्थिति में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर सकता है।

हाल ही मैं अमेरिका ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करने का प्रयास करेगा उस पर कठोर प्रतिबंध लगाये जा सकते है। इस बात का भारत पर भी व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है

→ भारत ईरान ~~के साथ~~ से उच्च स्तर पर तेल व गैस का आयात करता है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु अति महत्त्वपूर्ण है।

→ इससे भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे चाबहार बन्दरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा प्रोजेक्ट इत्यादि

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

पर व्यापक नकारात्मक पड़ने की संभावना है।

→ इन प्रतिबंधों में रूस पर प्रतिबंध भी शामिल है जिससे भारत-रूस संबंधो पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगे

→ भारत-रूस से व्यापक स्तर पर रक्षा उत्पादों को आयात करता है। अत: इन प्रतिबंधों के पश्चात भारत की सुरक्षा स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है

CAATSA एक ऐसा अमेरिकी अधिनियम है जो अपने शत्रु देशों जैसे उत्तरी कोरिया, ईरान, रूस इत्यादि ~~एक~~ के साथ व्यापार करने वाले अन्य देशों पर प्रतिबंध आरोपित करने का प्रावधान करता है।

हाल ही में ईरान व रूस पर इसके अन्तर्गत प्रतिबन्ध आरोपित किए गए जिनके नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए भारत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए -

(i) अमेरिकी नेतृत्व के साथ कूटनीतिक स्तर पर वार्ता करते हुए यह मुद्दा उठाना चाहिए कि ईरान व रूस के साथ उसके संबंध भारत की ऊर्जा सुरक्षा व सामरिक हितों हेतु अत्यावश्यक है तथा हिन्द महासागर पर चीन के प्रभाव को रोकने में अत्यन्त सहायक है

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका पर दबाव बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह इन एकतरफा प्रतिबंधों को वापस ले सके

(iii) '2+2 वार्ता' के मंच पर इन विषयों को दृढ़ता के साथ उठाना चाहिए

भारत को अपने आर्थिक व सामरिक हितों की रक्षा के लिए इन प्रतिबंधों से निपटने के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयास करने होंगे।